भारत सरकार

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय

भारी उद्योग विभाग

लोक सभा

तारांकित प्रश्न सं. 154*

गुरूवार, 07 मार्च, 2013

ऑटोमोबाइल क्षेत्र को पैकेज

***154. श्री मधु गौड यास्खी:**

श्री प्रदीप माझी:

क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश के ऑटोमोबाइल क्षेत्र को कोई प्रोत्साहन पैकेज देने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार को देश के ऑटोमोबाइल क्षेत्र के पुनरूद्धार हेतु विभिन्न हितधारकों से कोई सुझाव प्राप्त हुए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या मंत्रालय ने यह मामला वित्त मंत्रालय के साथ उठाया है; और

(ड.) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर वित्त मंत्रालय की क्या प्रतिक्रिया है तथा इस पैकेज को कब तक अंतिम रूप दे दिया जाएगा ?

उत्तर

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री

(श्री प्रफुल पटेल)

उत्तर (क) से (ड.) : विवरण सदन के पटल पर प्रस्तुत है ।

विवरण

ऑटोमोबाइल क्षेत्र को पैकेज के संबंध में श्री मधु गौड यास्खी और श्री प्रदीप माझी द्वारा दिनांक 07.03.2013 को पूछे जाने वाले लोक सभा के तारांकित प्रश्न सं. 154 के भाग (क) से (ड.) के उत्तर में संदर्भित विवरण ।

(क): जी, नहीं।

(ख): प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) से **(ड.):** सरकार उद्योग सहित सभी हितधारकों के साथ परामर्श करके ऑटोमोबाइल क्षेत्र के व्यापक और सतत विकास के लिए उपाय करती है। इस संबंध में, उद्योग सहित सभी हितधारकों के साथ विस्तारपूर्वक परामर्श करने के पश्चात सरकार द्वारा **ऑटो मिशन योजना 2006-16** तैयार की गई है। यह मिशन योजना इस क्षेत्र के लिए सरकारी नीति की आधारशिला है । इसके अतिरिक्त, देश में इस क्षेत्र को सुदृढ़ करने के लिए कई अन्य क्षेत्रों में पहल की गई है; जैसे कि **ऑटो सेक्टर दक्षता विकास परिषद (एएसडीसी)** की स्थापना करना; ऑटोमोटिव उपकर वित्तपोषण के माध्यम से अनुसंधान और विकास परियोजनाओं को सहायता देना, आधिकारिक रूप से प्रमाणन तथा परीक्षण के लिए विश्वस्तरीय अवसरंचना की स्थापना हेतु 2288 करोड़ रूपए से एक परियोजना अर्थात **राष्ट्रीय ऑटोमोटिव अनुसंधान और विकास अवसरंचना परियोजना (नैट्रिप)** आरंभ करना, ऑटो अनुसंधान और विकास विशेषज्ञता के भंडार तथा सहयोगपूर्ण अनुसंधान और विकास की आवश्यकता को पूरा करने और नैट्रिप केन्द्रों के कार्यकलापों को समन्वित करने के लिए शीर्ष समन्वयकारी निकाय के रूप में **राष्ट्रीय ऑटोमोटिव बोर्ड (एनएबी)** की स्थापना करना; नई अनुमोदित **नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन प्लान 2020** के माध्यम से पर्यावरण पर ईंधन उत्सर्जन के प्रभाव को कम करते हुए भावी ईंधन सुरक्षा सुनिश्चित करना । विभाग उपर्युक्त सभी कदमों के कार्यान्वयन की नियमित समीक्षा करता है और नीति निरुपण और कार्यान्वयन पर प्रत्येक वर्ष बजट में निधियों के पर्याप्त आबंटन के लिए वित्त मंत्रालय और योजना आयोग सहित संबंधित हितधारकों को सुझाव देता है ।

*****